Indian interests in Patent and Trade Marks Laws

482. DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have finalised a package of legal and administrative reforms to protect Indian interest in the Patents Laws and Trade Marks Laws;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the specific impediments/bottlenecks faced so far and the extent to which the contemplated changes will be an improvement in the desired direction?

THE MINISTER OF INDUSTRIES (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) to (c) Government have taken several measures to streamline, strengthen and modernise the patent and trade marks administration systems. It has already modernised its patent information services and trade marks registration systems. Steps are now underway to modernise the patent registration system which will ensure speedy disposal of applications.

Impact of sanctions on Industry

483. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have assessed the impact of various sanctions imposed by different countries against Indian industry following nuclear experiments of 11th and 13th May, 1998;

(b) if so, the details thereof; and

(c) steps taken by Government to neutralize them?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) to (c) The effect of the sanctions is being assessed on a continuing basis. Preliminary enquiries with the industry federations viz. CII, FICCI and ASSOCHAM indicate that they are not likely to have significant effect on Indian industry. The non-availability of US Exim Bank funds and insurance cover from Overseas Private Investment Corporation, may lead to switch over to normal commercial credit, which may be marginally costlier.

सार्वजनिक उपक्रमों को हुए घाटे

484. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी इकाइयां घाटे में चल रही हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की ऋण इकाइयों को लाभ में लाने के लिए कोई उपाय कर रही है; और

(ग) सरकार को वर्ष 1995-96, 1996-97 व 1997-98 में सार्वजनिक क्षेत्र एवं सरकारी उपक्रमों में कितना घाटा हुआ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार, जिस तारीख तक सूचना उपलब्ध है, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले उपक्रमों की संख्या 101 थी। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों द्वारा उठाए गए घाटे का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्ट 1995-96 के खण्ड-1 के विवरण संख्या 7ख में दिया गया है, जिसे पहले ही संसद के दोनों सदनों में दिनांक 5.5.1997 को प्रस्तुत कर दिया गया था।

(ख) जी, हां। सरकार ऋण तथा घाटा उठाने वाली इकाईयों का पुनरूद्धार करने के लिए सतत प्रयास कर रही है।

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान जिस अवधि की सूचना उपलब्ध है, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 101 उपक्रमों ने 4826.21 करोड़ रुपए का घाटा उठाया था।

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया में वित्तीय अनियमितताएं

485. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री रामगोपाल यादव:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1987 से 1997 के दौरान सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय घपले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इनकी जांच करा कर इस संबंध में किसी की जवाबदेही तय की है; और

(ग) इस संबंध में जांच रिपोर्ट और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) वित्तीय अनियमितताओं की कुछ घटनाएं सरकार के ध्यान में लाई गई हैं।